



# The ACHIEVERS IAS ACADEMY

LANGUAGE -HINDI

# CURRENT AFFAIR

16 - 09 - 2023

Saturday



## THE ACHIEVERS IAS ACADEMY

Patliputra Colony, Near Tennis Court; Patna, Contact : 8434931877, 7250667974

THE ACHIEVERS IAS ACADEMY



# DAILY

# CURRENT AFFAIRS

# &

# QUIZ



UPSC / BPSC

[www.achieversiaspatna.co.in](http://www.achieversiaspatna.co.in)

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY

## 1. सुब्रतो कप 2023: दिल्ली और गुरुग्राम के साथ बंगलुरु बना मेजबान शहर



सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, भारत की सबसे पुरानी नेशनल इंटर-स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता, अपने 62 वें संस्करण में इतिहास बनाने के लिए तैयार है। भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु को इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए मेजबान शहरों की सूची में जोड़ा गया है। इससे पहले दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2023 तक तीन स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। कई वर्षों से, सुब्रतो कप भारत में युवा फुटबॉल प्रतिभा का प्रदर्शन रहा है। इस साल टूर्नामेंट के आयोजकों ने बंगलुरु को अपने पाले में लाकर अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बंगलुरु में मैचों की मेजबानी करने का निर्णय देश के अधिक कोनों तक पहुंचने और विभिन्न क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी फुटबॉलरों को राष्ट्रीय मंच पर चमकने का अवसर देने के लिए टूर्नामेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंडर-17 जूनियर लड़कों और लड़कियों के टूर्नामेंट (दिल्ली-एनसीआर): अंडर -17 वर्ग के लिए मैच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अंबेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड (दिल्ली), सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड (दिल्ली) और जीडी गोयनका स्कूल (गुरुग्राम) जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर होंगे। इस वर्ग में भारतीय फुटबॉल की कुछ सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने की उम्मीद है। अंडर-14 सब-जूनियर लड़कों की प्रतियोगिता (बंगलुरु): बंगलुरु सब-जूनियर लड़कों के वर्ग की मेजबानी करेगा, जिसमें एएससी सेंटर, जलाहल्ली में वायु सेना स्कूल और येहलंका में वायु सेना स्कूल में मैच होंगे।

## 2. एमपी कैबिनेट ने मॉब लिंगिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी



मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में मॉब लिंगिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंगिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भोपाल में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत, मॉब लिंगिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन की आदतों, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। या अन्य ऐसे आधार या आधार या चोट पहुंचाने के इरादे से हिंसा के किसी भी कार्य या कृत्यों की श्रृंखला शामिल है। मॉब लिंगिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए योजना को लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत सरकार के सरकारी, स्वायत्त और सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों और उनके विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाधता को समाप्त कर दिया है। मंत्रि-परिषद ने भोपाल के 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु विशेष सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु कुल 195 पदों के सृजन एवं आवर्ती व्यय की मंजूरी दी है। साथ ही, सफाई जैसी गैर-प्रमुख सेवाओं के अलावा निगरानी, विद्युत रखरखाव और लिफ्ट संचालन, जल आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा और पाइपलाइन, कीट और पशु नियंत्रण, पार्किंग प्रणाली और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कपड़े धोने की व्यवस्था की व्यवस्था के लिए भी मंजूरी दी गई है। और 300 बिस्तरीय वाले सिविल अस्पताल में हाउसकीपिंग, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी।

## 3. अमेज़ॉन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY



भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programme) को और मजबूती मिलेगी। ऐमजॉन वेब सर्विसेज (AWS) ने क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा स्पेस-टेक इनोवेशंस में मदद करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE) के साथ एक स्ट्रेटेजिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस गठबंधन द्वारा स्पेस स्टार्टअप, शोध संस्थानों एवं विद्यार्थियों को अत्याधुनिक क्लाउड टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो सकेगी, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में नए समाधानों के विकास में तेजी लाएगी। ISRO, IN-SPACE, और AWS वित्तीय क्षेत्र के स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के लिए सहयोग करेंगे। AWS वेब सर्विसेस (AWS) एक्टिवेट प्रोग्राम के माध्यम से पात्र अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करेगा, जिसमें उपकरण, संसाधन, और तकनीकी मदद बिना कोई लागत के शामिल होंगे। इस समर्थन का उद्देश्य अद्वितीय अंतरिक्ष समाधानों के विकास और वाणिज्यिकरण की गति को तेजी से बढ़ाना है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स AWS स्पेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम के माध्यम से एडब्ल्यूएस के वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे, जिसमें एडब्ल्यूएस द्वारा एयरोस्पेस और सैटेलाइट समाधानों के निर्माण में विशेषज्ञता की विश्व स्तरीय जानकारी शामिल है। N-SPACE में प्रमोशन डायरेक्टोरेट के निदेशक विनोद कुमार ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला। चंद्रयान -3 चंद्रमा लैंडिंग और आदित्य एल -1 मिशन के बाद, यह सहयोग निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को सशक्त और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य भारत और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्लाउड कंप्यूटिंग की असीम क्षमता का उपयोग करना है।

**4. भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला बना 13वां देश**



भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाणपत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। ओआईएमएल एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। भारत 1956 में इसका सदस्य बना। इसके 63 सदस्य देश और 64 सहयोगी सदस्य हैं। भारत अब विश्व में कहीं भी बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ओआईएमएल प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए ओआईएमएल मॉडल अनुमोदन प्रमाणपत्र अनिवार्य है। यह अब उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदान किया जा सकता है। भारत ओआईएमएल की अनुशंसाओं तथा वजन एवं माप के परीक्षण और कैलिब्रेशन की प्रक्रियाओं का पालन करता है। वैधानिक भार एवं मापन (लीगल मेट्रोलॉजी) की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें अब ओआईएमएल जारी करने वाले अधिकारियों को स्वीकार्य हैं। इसके साथ ही भारत अब ओआईएमएल प्रारूप वाले अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है और स्वदेशी निर्माताओं के लिए सहायता प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है। घरेलू निर्माता अब किसी अतिरिक्त परीक्षण शुल्क के बिना ही अपने भार और माप उपकरणों को विश्व भर में निर्यात कर सकते हैं जिससे लागत में महत्वपूर्ण बचत होगी। भारत अब क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएलएस) से ओआईएमएल प्रारूप वाले अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करके विदेशी निर्माताओं का भी समर्थन कर सकता है। विदेशी निर्माताओं को भार एवं माप के ओआईएमएल प्रमाण पत्र जारी करके भारत अब शुल्क आदि से भी विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकेगा।

**5. कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए शुरू किया 4 लाख रुपये का बीमा कवर**

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY



कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के हितों और कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसमें एक समृद्ध बीमा पैकेज शामिल है जिसका मूल्य 4 लाख रुपये है, जिसमें 2 लाख रुपये की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा शामिल है। इस महत्वपूर्ण कदम का अपेक्षित फायदा होने की उम्मीद है कि लगभग 2.3 लाख गिग वर्कर्स को मिलेगा, जो Swiggy, Zomato जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और बिगबास्केट जैसे अग्रणी ई-कॉमर्स दिग्गज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। 'कर्नाटक स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम' नामक नई शुरू की गई पहल को कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा की गई 2023-24 की बजटीय घोषणा की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, एक लंबे समय से प्रतीक्षित उपाय जिसे पूरे राज्य में गिग श्रमिकों द्वारा गर्मजोशी से प्राप्त किया गया है। इस योजना के सबसे सराहनीय पहलुओं में से एक यह है कि पूरा वित्तीय बोझ सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि गिग वर्कर्स वित्तीय बाधाओं के बारे में चिंता किए बिना बहुत आवश्यक सुरक्षा प्राप्त कर सकें। इस पहल के लिए वित्त के प्राथमिक स्रोत में उपलब्धता के अधीन राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से अनुदान शामिल हैं। कर्नाटक राज्य गिग वर्कर्स बीमा योजना के तहत, गिग वर्कर्स कई लाभों का लाभ उठा सकते हैं। दुर्घटनाओं के मामलों में 1 लाख रुपये तक के अस्पताल के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी, चाहे वे झूटी पर हों या बाहर। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लाभ विशेष रूप से सक्रिय श्रमिकों पर लागू होते हैं। पात्र व्यक्तियों को दुर्घटना या मृत्यु के एक वर्ष के भीतर अपने आवेदन जमा करने होंगे।

**6. अभिनेता ऋतिक रोशन होंगे प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबी का नया चेहरा**



दुनिया की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और लागू करने की 150 साल की विरासत के साथ, एक्सॉन मोबिल ने अपने स्नेहन ब्रांड मोबिल™ के लिए अभिनेता ऋतिक रोशन को नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। रोशन, जो अपने आत्मविश्वास और बेजोड़ ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, ब्रांड के चेहरे के लिए एक स्पष्ट पसंद थे क्योंकि वह आत्मविश्वास बढ़ाने, मानव प्रगति को आगे बढ़ाने और ग्राहकों को उनकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम बनाने के मूल ब्रांड मूल्यों को प्रतिध्वनित करते हैं। मोबिल स्नेहन प्रौद्योगिकी नवाचार में सबसे आगे रहा है और विभिन्न बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ रूप से तैयार औद्योगिक स्नेहक की एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह ऋतिक रोशन और मोबिल ब्रांड के बीच पहला सहयोग नहीं है। इससे पहले, मोबिल ने अभिनेता की एक्शन थ्रिलर 'विक्रम वेधा' के साथ हाथ मिलाया, जहां फिल्म ने सूचित विकल्पों के माध्यम से कल्याण को प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। एक सदी से अधिक के लिए, मोबिल ने एक प्रौद्योगिकी नेता और विश्वसनीय भागीदार के रूप में दुनिया की लुब्रिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑटोमोबाइल, ट्रकों और मोटरसाइकिलों के लिए उत्कृष्ट इंजन प्रदर्शन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोबिल उत्पादों को सावधानीपूर्वक इंजीनियर किया जाता है। व्यापार क्षेत्र में, मोबिल ने लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और उपकरण दक्षता में सुधार करके दुनिया भर में विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों को सशक्त बनाया है। उत्कृष्टता के लिए मोबिल की प्रतिबद्धता वैश्विक स्तर पर उद्योगों की लुब्रिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत वाहनों से परे फैली हुई है।

**7. FIH ने पाकिस्तान से ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर वापस लिया**

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY



अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) पाकिस्तान से मेजबानी के अधिकार वापस लेने के बाद जल्द ही तीन पेरिस 2024 ओलंपिक क्वालीफायर में से एक के लिए एक नए मेजबान की घोषणा करेगा। पाकिस्तान हॉकी महासंघ से संबंधित मुद्दों के कारण एफआईएच ने पाकिस्तान से पुरुष ओलंपिक क्वालीफायर वापस ले लिया। "एफआईएच पुष्टि कर सकता है कि उसने जनवरी 2024 में होने वाले पुरुष एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान से वापस लेने के अपने फैसले के बारे में पाकिस्तान हॉकी महासंघ को सूचित कर दिया है। यह मुख्य रूप से शासन की स्थिति में हालिया विकास के कारण है। फेडरेशन. वैश्विक हॉकी नियामक संस्था ने एक बयान में कहा, "इस टूर्नामेंट के लिए नए मेजबान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अन्य क्वालीफायर जुलाई में घोषणा के अनुसार चीन और स्पेन में आयोजित किए जाएंगे।" पाकिस्तान को अगले साल की शुरुआत में चीन और स्पेन के साथ पुरुष ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी करनी थी। 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओलंपिक क्वालीफायर पाकिस्तान में पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय हॉकी आयोजन हो सकता था। तीन एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट में से प्रत्येक में शीर्ष 3 टीमों पेरिस 2024 के लिए क्वालीफाई करेंगी। वे मेजबान फ्रांस के साथ-साथ प्रत्येक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप (अफ्रीकी हॉकी रोड टू पेरिस, पैन अमेरिकन गेम्स, एशियन गेम्स, यूरोहॉकी चैंपियनशिप) के विजेताओं में शामिल होंगी। और ओशिनिया कप)। दुनिया में 15वें स्थान पर मौजूद पाकिस्तान को एशियाई खेलों में जीत हासिल करनी होगी या अन्यत्र आयोजित क्वालीफाइंग मैचों में अपनी भागीदारी की पुष्टि का इंतजार करना होगा।

8. कैबिनेट ने 4 साल के लिए ईकोर्ट्स चरण III को दी मंजूरी



भारत सरकार ने देश की न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। 7,210 करोड़ रुपये के पर्याप्त बजट आवंटन के साथ, इस पहल का उद्देश्य अदालतों की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ई-कोर्ट चरण III परियोजना के केंद्रीय उद्देश्यों में से एक डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट सिस्टम की ओर संक्रमण करना है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास विरासत दस्तावेजों सहित अदालत के रिकॉर्ड के पूरे स्पेक्ट्रम को डिजिटलाइज़ करना चाहता है। यह डिजिटल परिवर्तन अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी तक पहुंच में तेजी लाने के लिए तैयार है। ई-कोर्ट परियोजना की जड़ें 2007 से हैं और यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संचालित होती है। सुप्रीम कोर्ट नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और परियोजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है, जबकि न्याय विभाग (डीओजे) आवश्यक धन प्रदान करता है। 1,670 करोड़ रुपये के बजट वाली परियोजना के दूसरे चरण ने न्यायपालिका के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोविड-19 महामारी के उथल-पुथल भरे दौर में। इसने अदालत के संचालन में महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन पेश किया और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की शुरुआत की – एक भंडार जिसमें जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 23 करोड़ से अधिक मामले हैं। यह डेटा भंडार पारदर्शिता और न्यायिक जानकारी तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## QUIZ

1. हाल ही में भारत में किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है?

- A- फ्रांस
- B- अमेरिका
- C- चीन

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY

D- कोई नहीं

भारत लगातार चीन से आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। इससे भारतीय विनिर्माण कंपनियों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के दृढ़ बदलाव को दिखाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 2023 की पहली छमाही में चीन से सौर मॉड्यूल के आयात में 76 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। यह सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक ऊर्जा शोध संस्थान एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार, सालाना आधार पर चीन से भारत का सौर मॉड्यूल आयात 2022 की पहली छमाही में 9.8 गीगावॉट से घटकर 2023 में इसी अवधि में मात्र 2.3 गीगावॉट रह गया।

**2. हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है?**

A- असम

B- हिमाचलप्रदेश

C- उत्तराखंड

D- हरियाणा

असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के एक मोबाइल एप्लिकेशन ऐप 'सरपंच संवाद' का अनावरण किया। क्यूसीआई ने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में सरपंच संवाद शुरू किया, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है। इस पहल के माध्यम से, सरपंच अपने गांवों में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं और देश भर में कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं।

**3. विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस (WLAD) ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है?**

A- 15 सितंबर

B- 13 सितंबर

C- 14 सितंबर

D- 11 सितंबर

विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस (WLAD) 15 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, रक्त कैंसर का एक समूह जो लसीका प्रणाली को प्रभावित करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक

महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिम्फोमा विभिन्न रूपों में आते हैं, जिसमें हॉजकिन लिम्फोमा और गैर-हॉजकिन लिम्फोमा दो मुख्य प्रकार हैं। WLAD लिम्फोमा के बारे में जनता को शिक्षित करने का प्रयास करता है, जिसमें इसके प्रकार, लक्षण, जोखिम कारक और उपलब्ध उपचार विकल्प शामिल हैं। बढ़ी हुई जागरूकता से लिम्फोमा से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए पहले निदान और बेहतर परिणाम हो सकते हैं।

**4. हाल ही में किसने 'स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया है?**

A- नरेंद्र मोदी

B- धर्मेंद्र प्रधान

C- निर्मला सीतारमण

D- कोई नहीं

प्रत्येक भारतीय के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास, प्रासंगिक अवसर तक पहुंच और उद्यमशीलता समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) का शुभारम्भ किया। यह एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य के बीच तालमेल बिठाना और बदलाव लाना है। यह प्लेटफॉर्म उन लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है जो अपने लिए बेहतर अवसर और उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं। यह प्लेटफॉर्म उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर भी उपस्थित थे।

**5. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है?**

A- गुजरात

B- असम

C- राजस्थान

D- कोई नहीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NEVA के शुभारंभ के बाद विधायकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 'वन नेशन वन एप्लीकेशन' सदन के कामकाज में गति और पारदर्शिता लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY

जनप्रतिनिधियों को उनके स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिकों के सामने आने वाले स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से उठाने में मदद करेगी। इसे गुजरात का उत्कृष्ट कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि यह असेंबली डिजिटल हाउस में तब्दील हो जाएगी।

6. हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक 'द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है?

A- विनोद मंकारा

B- सारिका भारद्वाज

C- लीना कुमार

D- कोई नहीं

लेखिका, लीना कुमार, एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, पटकथा लेखक और उद्यमी हैं, जो 25 वर्षों से अधिक के करियर में भारतीय सिनेमा पर अपने प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। "द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड" तर्कसंगत, व्यावहारिक, साधक, गैर-अनुरूपतावादियों, नेताओं, अप्रदूतों, विद्रोहियों और स्वतंत्र आत्माओं के लिए है। 16 साल की उम्र से अभिनय की दुनिया में कदम रखने के बाद, उन्होंने पांच भाषाओं में 175 से अधिक फिल्मों में काम किया है, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में ब्लॉकबस्टर और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिया है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, मी-ब्रांड एक्सेलेरेटर अवॉर्ड्स, SIIMA अवॉर्ड्स, IIFA अवॉर्ड, टोरंटो इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म अवॉर्ड्स, केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स और केरल फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवॉर्ड्स शामिल हैं।

7. हाल ही में किस नगर निगम नायक 'कैश फॉर वेस्ट योजना' शुरू की है?

A- पुणे

B- लखनऊ

C- पटना

D- कोई नहीं

पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है क्योंकि इसे महिला श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। इस सुविधा में प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला

कचरा संसाधित करने की क्षमता है। पिंक एमआरएफ की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जर्मन संस्था जीआईजेड और अन्य संगठनों के सहयोग से पटना नगर निगम (पीएमसी) द्वारा की गई है।

8. राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कब एक विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया?

A- 15 सितंबर

B- 13 सितंबर

C- 12 सितंबर

D- 14 सितंबर

विशेष अभियान 3.0 की निगरानी के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में एक समर्पित वेब पोर्टल- <https://scdpm.nic.in> लॉन्च किया गया। सरकार ने इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 3.0 की घोषणा की है। इसे स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए शुरू किया जा रहा है। विशेष अभियान 3.0 से पहले 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक प्रारंभिक चरण चलाया जाएगा। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय/विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करेंगे और अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे।

## ONE LINER

सबसे तेज 150 वन डे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कंपनी है - कुलदीप यादव

किस देश की वायुसेवा को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा - भारत

किसने पाँचवी बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रगबी चैंपियनशिप जीती है - महाराष्ट्र

हाल ही में ITIA ने सिमोना हैलेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबन्ध लगाया है - 04

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है - नई दिल्ली

हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डर्ना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है - लीबिया

किससे NASSCOM के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है - सिंधु गंगाधरन

किस नगर निगम नायक 'कैश फॉर वेस्ट योजना' शुरू की है - पटना

हाल ही में इसबार 'नौसेना दिवस' किस किले में मनाया जाएगा - सिंधु दुर्ग किला

# THE ACHIEVERS IAS ACADEMY

---

किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है -- **उत्तर प्रदेश**

किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है -- **असम**  
हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदार बैठक कहां होगी - **मुंबई**

